नईदुनिया

संपादकीय

दिया तले अंधेराः फर्जी डॉक्टरों का गोरखधंधा

स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

स्वास्थ्य सेवा किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जाती है, क्योंकि यह सीधे आमजन के जीवन और मृत्यु से जुड़ी होती है। जब इसी पवित्र क्षेत्र में फर्जीवाड़ा पनपने लगे और फर्जी डिग्रीधारी लोग सरकारी नियमों को धता बताकर सरकारी योजनाओं में नियुक्ति प्राप्त कर लें, तो समझा जा सकता है कि व्यवस्था कितनी खोखली हो चुकी है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में फर्जी डॉक्टरों और फर्जी नियुक्तियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो न केवल सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि मरीजों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं।

हाल का मामला विभागीय लापरवाही का बड़ा उदाहरण है, जिसमें एक व्यक्ति ने तीन अलग-अलग जिलों में अलग कर्मचारी आईडी, अलग पैन नंबर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर नौकरी की तथा सरकारी खजाने से लाखों रुपये वेतन के रूप में प्राप्त किए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार सरकार को लगभग 64 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े के बावजूद विभाग की जांच प्रणाली वर्षों तक इसे पकड़ नहीं सकी। न ऑनलाइन प्रणाली में कोई गड़बड़ी सामने आई और न ही जिला या राज्य स्तर पर किसी अधिकारी को संदेह हुआ। यह स्पष्ट करता है कि स्वास्थ्य विभाग में दस्तावेजों के सत्यापन और क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रभावी व्यवस्था नहीं है। चिंता की बात यह भी है कि फर्जी डॉक्टर केवल वेतन ही नहीं ले रहा था, बल्कि मरीजों का उपचार भी कर रहा था। बिना वैध चिकित्सा डिग्री वाला व्यक्ति यदि दवा लिखे, इंजेक्शन लगाए या गंभीर बीमारियों का इलाज करे, तो उसके दुष्परिणाम घातक हो सकते हैं। गलत निदान या गलत दवा किसी की जान भी ले सकती है। इसलिए यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक कृत्य है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नियुक्ति के समय दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल डिग्री की प्रमाणिकता की जांच कैसे नहीं हुई। यदि सभी प्रक्रियाएं पूरी हुई थीं, तो यह व्यक्ति तीन स्थानों पर नौकरी कैसे करता रहा? स्पष्ट है कि प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं या फिर कहीं न कहीं मिलीभगत रही है। संविदा और एनएचएम की नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। आरोपी की सेवा समाप्त करने, वेतन की वसूली और एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन केवल एक मामले में कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। आवश्यकता है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए तथा उनकी डिग्री, आधार और अन्य अभिलेखों का केंद्रीय स्तर पर सत्यापन किया जाए।

जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, ऐसे मामले रुकने वाले नहीं हैं। प्रत्येक जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करनी होगी। नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, ताकि मानवीय हस्तक्षेप और फर्जीवाड़े की गुंजाइश समाप्त हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं में फर्जीवाड़ा सीधे जनता के जीवन से जुड़ा अपराध है। अब समय आ गया है कि सरकार इसे एक अकेला मामला न मानकर पूरे तंत्र की व्यापक समीक्षा करे, ताकि जनता का भरोसा स्वास्थ्य व्यवस्था पर बना रहे।

आजकल

विकास की बाट जोह रहा रामपथगमन कछुआ चाल ने तोड़ा श्रद्धालुओं का धैर्य

चित्रकूट को प्रभु श्रीराम की तपोभूमि के रूप में विश्वभर में मान्यता प्राप्त है, लेकिन विडंबना यह है कि यहां विकास कार्य कछुआ गति से चल रहे हैं। कामदगिरि परिक्रमा पथ और मंदाकिनी घाटों के निर्माण की धीमी रफ्तार ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का धैर्य तोड़ दिया है। एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद परिक्रमा पथ के ढाई किलोमीटर हिस्से का कार्य भी पूरा नहीं हो सका है। निर्माण स्थल पर जगह-जगह बालू, सीमेंट और गिट्टी के ढेर लगे होने से श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उबड़-खाबड़ और फिसलन भरे मार्ग के कारण कई बुजुर्ग और महिलाएं चोटिल हो चुके हैं। यह केवल निर्माण में देरी का मामला नहीं, बल्कि आस्था से जुड़े स्थान पर गंभीर लापरवाही का उदाहरण है। स्थिति यह है कि जब भी प्राधिकरण के अध्यक्ष या कलेक्टर समीक्षा बैठक के लिए आते हैं, तब एक दिन पहले निर्माण कार्य में तेजी दिखाई देती है। बैठक समाप्त होते ही काम फिर ठप पड़ जाता है। यही कारण है कि चित्रकूट की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। सीवर लाइन परियोजना इसका प्रमुख उदाहरण है।

समस्या की जड़ जवाबदेही का अभाव है। ठेकेदारों पर समयसीमा का पालन कराने और अधिकारियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। निर्माण सामग्री को रास्ते से हटाकर श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया जाना चाहिए तथा देरी होने पर आर्थिक दंड और ब्लैकलिस्टिंग जैसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चित्रकूट केवल एक नगर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। रामपथगमन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। विकास की यह कछुआ चाल अब तेज गति में बदलनी ही होगी, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास दोनों सुरक्षित रह सकें।

ई-20 का ढोल और उपभोक्ता पर प्रहार

आत्मनिर्भरता के नाम पर मध्यमवर्ग की जेब पर डाका

देश आत्मनिर्भर बने, किसान खुशहाल हो और प्रदूषण कम हो, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सरकार ने यही सोचकर ई-20 पेट्रोल को पूरे देश में लागू किया, पर जमीनी हकीकत यह है कि इस आत्मनिर्भरता की कीमत आज वही चुका रहा है, जिसके पास पहले से कुछ नहीं बचा था। वह है मध्यमवर्गीय उपभोक्ता। सर्विस सेंटरों के बाहर लगी लंबी लाइनें चीख-चीखकर एक ही बात कह रही हैं कि ई-20 पेट्रोल ने पुरानी गाड़ियों की कमर तोड़ दी है। सरकार कह रही है कि ई-20 से कच्चे तेल का आयात घटेगा और विदेशी मुद्रा बचेगी। चीनी मिलें और इथेनॉल कंपनियां कह रही हैं कि अब फसल का सही दाम मिलेगा। कार कंपनियां कह रही हैं कि 2023 के बाद बने सभी इंजन ई-20 के अनुरूप हैं, इसलिए नई गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं। सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं कि काम बढ़ गया है, इसलिए धंधा चमक गया है।

उधर उपभोक्ता कह रहा है कि टंकी फुल कराते ही माइलेज गिर गया। वह कह रहा है कि कार्बोरेटर, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और रबर पाइप एक के बाद एक खराब हो गए। वह कह रहा है कि हर महीने पेट्रोल का बिल तो बढ़ा ही, अब सर्विस का बिल भी घर का बजट बिगाड़ रहा है। यही है ई-20 की हकीकत-कहीं खुशी, कहीं गम और बीच में पिस रहा आम आदमी। सर्विस सेंटरों की पड़ताल बताती है कि जून से जुलाई के बीच फ्यूल सिस्टम की शिकायतें 20 प्रतिशत बढ़ गई हैं। पहले जहां एक दिन में 25 से 30 गाड़ियां आती थीं, अब 50 से 55 गाड़ियां रोज आ रही हैं। फ्यूल फिल्टर साफ कराने वाली गाड़ियों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो गई है। सबसे ज्यादा मार उन वाहनों पर पड़ी है, जो पांच से सात साल पुराने हैं। कंपनियों का तर्क है कि यह सामान्य घिसावट है और समय पर सर्विस न कराने से ऐसा होता है। पर उपभोक्ता पूछता है कि घिसावट अचानक ई-20 आने के बाद ही क्यों बढ़ी? उपभोक्ता पूछता है कि अगर नई गाड़ियों में दिक्कत नहीं है, तो देश में दौड़ रही 80 प्रतिशत पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? क्या उन्हें कबाड़ में बेच दिया जाए? यह मानने में कोई बुराई नहीं कि इथेनॉल से किसान को फायदा होगा और देश को ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नीति बनाते समय उपभोक्ता को क्यों भुला दिया गया? पूरे देश में एक साथ ई-20 लागू कर दिया गया। पेट्रोल पंप पर विकल्प नहीं दिया गया। अगर आपकी गाड़ी ई-20 के अनुकूल नहीं है, तब भी आपको वही पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। यह जबरदस्ती नहीं तो क्या है?

उपभोक्ता कह रहा है कि टंकी फुल कराते ही माइलेज गिर गया। वह कह रहा है कि कार्बोरेटर, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और रबर पाइप एक के बाद एक खराब हो गए। वह कह रहा है कि हर महीने पेट्रोल का बिल तो बढ़ा ही, अब सर्विस का बिल भी घर का बजट बिगाड़ रहा है। यही है ई-20 की हकीकत-कहीं खुशी, कहीं गम और बीच में पिस रहा आम आदमी। सर्विस सेंटरों की पड़ताल बताती है कि जून से जुलाई के बीच फ्यूल सिस्टम की शिकायतें 20 प्रतिशत बढ़ गई हैं। पहले जहां एक दिन में 25 से 30 गाड़ियां आती थीं, अब 50 से 55 गाड़ियां रोज आ रही हैं। फ्यूल फिल्टर साफ कराने वाली गाड़ियों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो गई है। सबसे ज्यादा मार उन वाहनों पर पड़ी है, जो पांच से सात साल पुराने हैं।

कंपनियों को पहले से यह निर्देश नहीं दिया गया कि वे 2023 से पहले बिके वाहनों के लिए मुफ्त अपग्रेड किट दें। आज वही किट सर्विस सेंटर हजारों रुपये में बेच रहे हैं और उपभोक्ता लाचार होकर उसे खरीद रहा है। माइलेज गिरने की भरपाई के लिए पेट्रोल पर टैक्स में भी कोई राहत नहीं दी गई। जब खर्च बढ़ रहा है, तो कम से कम टैक्स तो कम किया जाए, पर वहां भी चुप्पी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इथेनॉल में नमी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। इससे फ्यूल सिस्टम में जंग लगती है, रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स जल्दी खराब होते हैं और माइलेज दो से तीन किलोमीटर प्रति लीटर तक गिर सकता है। कंपनी इसे तकनीकी बात कहकर टाल देती है, पर घर चलाने वाले को हर किलोमीटर की कीमत पता होती है। एक तरफ पेट्रोल महंगा, दूसरी तरफ माइलेज कम और तीसरी तरफ सर्विस का खर्च-इन सबने मध्यमवर्ग के बजट की रीढ़ तोड़ दी है। फायदा किसको हुआ? सरकार को, क्योंकि आयात बिल घटा। किसान को, क्योंकि गन्ने का भुगतान समय पर हुआ। इथेनॉल प्लांट मालिकों को, क्योंकि फैक्ट्रियां 24 घंटे चल रही हैं। कार कंपनियों को, क्योंकि लोग नई ई-20 अनुरूप गाड़ियां खरीदने को मजबूर हैं। सर्विस सेंटरों को, क्योंकि रिपेयरिंग का काम दोगुना हो गया।

नुकसान किसको हुआ? उसको, जिसने 2019 में कर्ज लेकर गाड़ी ली थी। उसको, जो रोज 40 किलोमीटर नौकरी के लिए बाइक चलाता है। उसको, जो हर महीने घर का हिसाब मिलाता है और पाता है कि 2,000 रुपये पेट्रोल में और 3,000 रुपये सर्विस में चले गए। समय रहते आंखें न खोली गईं, तो उपभोक्ता का भरोसा टूट जाएगा। पेट्रोल पंप पर ई-10 और ई-20 दोनों का विकल्प दिया जाए, ताकि जिसकी गाड़ी पुरानी है, वह अपना पेट्रोल चुन सके। सरकार कंपनियों पर दबाव बनाए कि वे 2023 से पहले के सभी वाहनों के लिए फ्यूल सिस्टम अपग्रेड किट मुफ्त में दें। इसकी लागत कंपनियां और सरकार मिलकर उठाएं। जब तक माइलेज की समस्या बनी हुई है, तब तक पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में राहत दी जाए, ताकि उपभोक्ता को थोड़ी राहत मिल सके। एक स्वतंत्र एजेंसी से ई-20 के प्रभाव पर अध्ययन कराया जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि सच और अफवाह में फर्क पता चल सके। विकास का मतलब सिर्फ बड़े आंकड़े नहीं होता। विकास का मतलब यह भी होता है कि आम आदमी का चूल्हा जलता रहे। ई-20 अपने आप में खराब नीति नहीं है, लेकिन उसे लागू करने की जल्दबाजी, उपभोक्ता को अंधेरे में रखना और यह सोच कि किसान खुश है तो उपभोक्ता अपने आप निपट लेगा, उचित नहीं कही जा सकती।

देश में दो भारत दिख रहे हैं। एक भारत जश्न मना रहा है कि हम इथेनॉल के क्षेत्र में दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा भारत सर्विस सेंटर के बिल को देखकर सिर पकड़ रहा है। सरकार को तय करना है कि उसे किस भारत के साथ खड़ा होना है। अगर ई-20 का ढोल इसी तरह बजता रहा और उपभोक्ता का घाव इसी तरह रिसता रहा, तो एक दिन लोग कहेंगे कि आत्मनिर्भरता के नाम पर हमारी जेब काट ली गई। और तब न तो कोई नीति बचेगी और न ही किसी नीति पर भरोसा। इसलिए अभी भी वक्त है। सुधार कीजिए, विकल्प दीजिए और उपभोक्ता को इस जश्न में शामिल कीजिए, वरना यह जश्न सिर्फ कागजों और भाषणों तक ही रह जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

दक्षिणी कमान अलर्टः मल्टी डोमेन युद्ध की तैयारी तेज

देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। कमांडर ने हाल ही में कमान क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मल्टी डोमेन युद्ध की संकल्पना और सुदर्शन चक्र कोर की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया। दक्षिणी कमान सेना की सबसे बड़ी कमानों में से एक है। इसका जिम्मा पश्चिमी और दक्षिणी, दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का है। इसलिए यहां की हर तैयारी का सीधा असर देश की सुरक्षा पर पड़ता है।

आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं है। अब साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध भी उतने ही अहम हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना ने मल्टी डोमेन युद्ध की रणनीति अपनाई है। कमांडर ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में युद्ध एक साथ कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा, इसलिए सेना को हर क्षेत्र में पूरी तरह तैयार रहना होगा। जमीन पर ताकत के साथ-साथ दुश्मन के साइबर नेटवर्क को भी निष्क्रिय करना होगा। अंतरिक्ष से निगरानी कर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी और सूचना युद्ध के माध्यम से उसके मनोबल को कमजोर करना होगा। उन्होंने कहा कि तकनीक अब युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। इसलिए दक्षिणी कमान में नई तकनीक और आधुनिक हथियारों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दौरे के दौरान कमांडर ने सुदर्शन चक्र कोर का भी निरीक्षण किया। यह कोर दक्षिणी कमान की प्रमुख स्ट्राइक फोर्स है। युद्ध की स्थिति में यह सबसे पहले दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई करने वाली इकाइयों में शामिल होती है। कमांडर ने जवानों से सीधे बातचीत की और उनके जोश की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र कोर की गति और ताकत देश की सुरक्षा की गारंटी है।

निरीक्षण के दौरान हथियारों, गोला-बारूद और संचार व्यवस्था की जांच की गई। सभी यूनिटों को 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। सेना में आधुनिकीकरण का काम तेजी से चल रहा है। नए हथियार, नए वाहन और नई संचार प्रणालियां जवानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सेना में शामिल किया जा रहा है। कमांडर ने कहा कि अब युद्ध में ड्रोन की भूमिका बहुत बढ़ गई है, इसलिए एंटी-ड्रोन सिस्टम को और मजबूत करना जरूरी है। साथ ही अपने ड्रोन के माध्यम से निगरानी और हमले की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी।

साइबर सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सेना के सभी नेटवर्क को सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि दुश्मन साइबर हमला न कर सके। सूचना युद्ध के लिए जवानों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कमांडर ने जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से ही देश सुरक्षित है। आपकी मेहनत और त्याग को पूरा देश सलाम करता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण का स्तर और ऊंचा किया जाए। हर जवान को नई तकनीक का ज्ञान हो और युद्ध जैसी परिस्थितियों का लगातार अभ्यास कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति में कोई चूक न हो।

जवानों के परिवारों के कल्याण पर भी जोर दिया गया। उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के आदेश दिए गए। दक्षिणी कमान की जिम्मेदारी सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि समुद्री तट की सुरक्षा भी है। पड़ोसी देशों की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कमांडर ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। सीमा क्षेत्रों में नए रडार और सेंसर लगाए गए हैं। नौसेना और तटरक्षक बल के साथ समन्वय भी मजबूत किया गया है।

आधुनिक युद्ध के लिए मजबूत लॉजिस्टिक्स जरूरी है। इसलिए दक्षिणी कमान क्षेत्र में सड़कों, पुलों और हवाई पट्टियों का निर्माण तेजी से हो रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना और हथियारों को तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। कमांडर ने सभी निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और समय पर उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए।

भविष्य का युद्ध पूरी तरह बदल चुका है। अब बंदूक और टैंक के साथ साइबर हमले और मिसाइल हमले भी होंगे। इसलिए दक्षिणी कमान खुद को नई पीढ़ी के युद्ध के लिए तैयार कर रही है। नई तकनीक, नए हथियार और नया प्रशिक्षण इसके तीन मुख्य आधार हैं। कमांडर ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दक्षिणी कमान देश की सबसे आधुनिक और सक्षम कमान बने।

दौरे के अंत में कमांडर ने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जवानों के साथ मिलकर काम करें, उनकी हर समस्या को गंभीरता से सुनें और उसका समाधान करें। दक्षिणी कमान का यह दौरा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है। मल्टी डोमेन युद्ध, साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीक पर फोकस करके सेना खुद को नए दौर के अनुरूप ढाल रही है। सुदर्शन चक्र कोर की मजबूती और जवानों का जोश इस बात की गारंटी है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज के समय में मजबूत सेना ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और दक्षिणी कमान उस ताकत को और धार देने में जुटी है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

84 महादेव दर्शन यात्रा

84/39 महादेव शृंखलाः अक्रूरेश्वर महादेव की प्रेरणादायक कथा

'अर्धनारीश्वर रूप ने सिखाया जीवन का सबसे बड़ा पाठ'

डॉ. नवीन आनंद जोशी

उज्जैन की पावन भूमि महाकाल वन में जब एक बार समस्त देवी-देवता, इंद्र, किन्नर और मुनिगण माता पार्वती की स्तुति में लीन थे, तब शिवजी के एक गण भृंगिरिट ने अहंकारवश जगतजननी पार्वती की स्तुति करने से साफ इनकार कर दिया। माता पार्वती ने अत्यंत स्नेह और धैर्य के साथ उसे कई बार समझाने का प्रयास किया कि वह स्वयं उनका पुत्र है, और केवल शिव की आराधना से ही उसका कल्याण संभव नहीं-माता और पिता, दोनों की कृपा और आशीर्वाद के बिना जीवन का पूर्ण होना असंभव है।

किंतु क्रूर बुद्धि और अहंकार में डूबा भृंगिरिट माता की इस अमूल्य सीख को समझ नहीं पाया, और योग विद्या के बल पर अपने शरीर का संपूर्ण मांस माता पार्वती को अर्पित कर केवल अस्थि-मात्र शेष रखकर शिवजी के समीप जा पहुँचा। यह केवल एक योगिक प्रयोग नहीं था, यह माता पार्वती के अस्तित्व और उनके सम्मान को नकारने का दुस्साहस था। माता पार्वती ने इस अपमान से क्षुब्ध होकर भृंगिरिट को श्राप दिया कि उसकी इसी क्रूर और अहंकारी बुद्धि के कारण उसे मनुष्य लोक में गिरना होगा। श्राप के प्रभाव से भृंगिरिट तत्काल पृथ्वी लोक पर आ गिरा, और तब उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने श्राप मुक्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी, परंतु भगवान शिव ने स्वयं उससे स्पष्ट कह दिया कि जिस माता का तुमने अनादर किया है, श्राप से मुक्ति भी केवल उन्हीं की कृपा से संभव है -अतः जाओ और माता पार्वती की आराधना करो। यह प्रसंग इस सत्य को उजागर करता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों की शक्ति समान और अविभाज्य है, और एक के बिना दूसरे की पूर्णता असंभव है।

भृंगिरिट ने शिवजी के निर्देशानुसार महाकाल वन में पहुँचकर पूर्ण विनम्रता और श्रद्धा के साथ शिवलिंग की उपासना आरंभ की। उसकी सच्ची तपस्या और हृदय से उपजे पश्चाताप को देखकर उस शिवलिंग से माता पार्वती और भगवान शिव का वह दिव्य अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा माता पार्वती का था -यह दृश्य स्वयं इस बात का प्रमाण था कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब नारी और पुरुष दोनों को समान आदर और स्थान प्राप्त हो। इसी अर्धनारीश्वर रूप ने भृंगिरिट को श्राप से मुक्त किया और उसकी क्रूर बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर दिया। कृतज्ञता से भरकर भृंगिरिट ने वरदान माँगा कि जिस शिवलिंग के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि शुद्ध हुई, वह शिवलिंग संसार में अक्रूरेश्वर के नाम से विख्यात हो। शिवजी ने यह वरदान सहर्ष स्वीकार किया, और तब से मान्यता चली आ रही है कि जो भी श्रद्धालु अक्रूरेश्वर महादेव के दर्शन-पूजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है।

यह पौराणिक कथा आज के युग के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितनी सतयुग में रही होगी। भृंगिरिट की भूल हमें यह सिखाती है कि जीवन में माता और पिता, दोनों को समान आदर और सम्मान देना अनिवार्य है -किसी एक का अनादर करके दूसरे की कृपा से जीवन को सफल बना लेना केवल एक भ्रम है, जैसा भृंगिरिट ने सोचा था। आज की पीढ़ी में यह कृतज्ञता का भाव कहीं न कहीं क्षीण होता जा रहा है -हम भूलते जा रहे हैं कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे उसकी अर्धांगिनी का भी उतना ही योगदान और सम्मान होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे माता पार्वती और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें सिखाता है कि नारी और पुरुष वस्तुतः एक ही सत्ता के दो अभिन्न रूप हैं। भृंगिरिट ने एक शॉर्टकट अपनाया -उसने केवल शिव से वरदान पाने की चाह में उस शक्ति को ही नकार दिया, जिसके बिना कोई भी वरदान स्थायी और सार्थक नहीं हो सकता। अंततः स्वयं भगवान महाकाल ने भी उसे यही मार्ग दिखाया कि माता पार्वती की स्तुति किए बिना उसका कल्याण असंभव है, और जब भृंगिरिट ने अपना अहंकार त्यागकर माता की आराधना की, तभी उसे वास्तविक मुक्ति प्राप्त हुई। उसी श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक स्वरूप अक्रूरेश्वर महादेव के रूप में यह शिवलिंग आज भी उज्जैन की पावन धरा पर स्थापित है, और हमें यह शाश्वत सीख देता है कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति तभी संभव है जब हम माता-पिता, स्त्री-पुरुष -दोनों को समान आदर, सम्मान और कृतज्ञता का भाव अर्पित करें।

निरंतर जारी...